बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-418
18/08/2020

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक–सह–प्रयोगशाला भवनों का किया उद्घाटन

- मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिन्दु :–
- मुख्य प्रशासनिक भवनों के साथ अन्य भवनों का उद्घाटन हुआ है जिस पर 268 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

- बिहार के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत जरुरी है।

- कृषि रोड मैप लागू होने से फसलों का उत्पादन और उनकी उत्पादकता दोनों बढ़ी है।

- मखाना पर और काम करने की जरूरत है। मखाना से देश भर को लगाव है। इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता और बढ़े। हमलोगों का सपना है कि हर भारतीय थाल में एक बिहारी व्यंजन जरुर हो।

- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अब राष्ट्रीय रैंकिंग में 18वें नंबर पर आ गया है।

- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान के लिए सबौर अर्द्ध जल एवं गेहूं के लिए सबौर निर्जल प्रभेद विकसित किये गये हैं, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

- जर्दालु आम, कतरनी चावल, मगही पान एवं शाही लीची को पेटेंट कर जी आई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार के विशिष्ट

उत्पाद मखाना भी जल्द से जल्द जी आई टैग प्राप्त करने की सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

- मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसे राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित करने को लेकर योजना बनाई जा रही है।

- पर्यावरण संरक्षण के लिए हमलोगों ने जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरुआत की है। जल–जीवन–हरियाली अभियान का मतलब है कि जल है, हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है।

- फसल अवशेष (पराली) जलाने से हो रहे पर्यावरण को नुकसान से बचाव के लिए किसानों को जागरूक करना होगा।

पटना 18 अगस्त 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक–सह–प्रयोगशाला भवनों का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मुख्य प्रशासनिक भवन एवं अन्य भवनों के उद्घाटन कराने के लिए बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि महाविद्यालय सबौर की स्थापना वर्ष 1908 में की गई थी और ये देश के पहले 5 कृषि महाविद्यालयों में से एक है। कृषि महाविद्यालय सबौर को 5 अगस्त 2010 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के रुप में परिणत किया गया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो कि अब डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रुप में परिणत हो गया है, यह कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1905 में समस्तीपुर जिले के एक गांव में यू0एस0ए0 के हेनरी फिप्स के सहयोग से इंपिरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रुप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1934 में भूकंप के कारण हुए नुकसान के बाद वर्ष 1936 में इस संस्थान को दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1970 में पूसा समस्तीपुर में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ0 राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रुप में परिणत करने के पश्चात हमलोगों ने निर्णय लिया कि बिहार में एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो और इसे सबौर में ही स्थापित किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से जुड़े हुए और 5 नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, सहरसा में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, डुमरांव

में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय तथा किशनगंज में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 कलाम साहब के निधन के अगले दिन ही उनके सम्मान में उनके नाम पर ही किशनगंज महाविद्यालय का नाम डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय करने का निर्णय लिया गया, जहां 10 अगस्त 2015 से ही पढ़ाई शुरु की गई। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय जैसा बड़ा कैंपस पूरे देश में कही नहीं है। पटना में बनने वाले साइंस सिटी का नामकरण भी डॉ0 कलाम साहब के नाम पर किया गया है। वर्ष 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। मुंगेर में बिहार वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुख्य प्रशासनिक भवनों के साथ अन्य भवनों का उद्घाटन हुआ है जिस पर 268 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। प्रशासनिक भवन के साथ–साथ 3 प्रयोगशाला भवन, छात्राओं के लिए हॉस्टल, वैज्ञानिकों तथा विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए आवास का निर्माण किया गया है। सभी प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किये गये हैं। स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है। विश्वविद्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ–साथ भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 89 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। बिहार की 76 प्रतिशत आबादी की जीविका का आधार कृषि है। हमलोगों का मानना है कि बिहार के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत जरुरी है। हमलोगों ने कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। अभी तक 3 कृषि रोड मैप बनाये गये हैं। वर्ष 2008–12 में प्रथम कृषि रोड मैप, वर्ष 2012–17 में दूसरा कृषि रोड मैप और वर्ष 2017–22 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप को लागू किया गया है। इससे फसलों की उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है। बिहार के कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुष क्रांति लाई गई और उससे बढ़ते हुए रजत क्रांति यानि अंडे का उत्पादन भी हुआ है। राज्य में धान, गेहूं, मक्के, फल, सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ मछली और अंडे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा की तरफ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए गये हैं। वर्ष 2012 से कृषि स्नातक की पढ़ाई में 2 हजार प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 6 हजार प्रति वर्ष किताबें खरीदने के लिए राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अब राष्ट्रीय रैंकिंग में 18वें नंबर पर आ गया है। यहां बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष खरीफ सीजन में 10 हजार क्विंटल से अधिक बीज वितरित किया गया है। टीशू क्लचर केले के उत्पादन में इस संस्थान की अहम भूमिका है। इस वर्ष जी 9 प्रजाति के 7 लाख से अधिक टीशू कल्चर केले के पौधे उत्पादित कर किसानों एवं अन्य विभागों को उपलब्ध कराया गया है। 8 लाख से अधिक आम, अमरुद, सहजन, केला की पौध सामग्री वन विभाग के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करायी गई है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में नये अनुसंधान कार्य शुरु किये गये हैं। धान के लिए सबौर अर्द्ध जल एवं गेहूं के लिए सबौर निर्जल प्रभेद विकसित किया गया है। जर्दालु आम, कतरनी चावल, मगही पान एवं शाही लीची को पेटेंट कर जी आई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार के विशिष्ट उत्पाद मखाना भी जल्द से जल्द जी आई टैग प्राप्त करने की सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मखाना के उत्पादन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। हमलोगों का सपना है कि हर भारतीय थाल में एक बिहारी व्यंजन जरुर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन के परिणामस्वरुप असमय वर्षा, अतिवृष्टि, सुखाड़, वज्रपात आदि के रुप में दिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमलोगों ने

जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान पर 24,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 10 कार्यों को शामिल किया गया है। जल–जीवन–हरियाली अभियान का मतलब है कि जल है, हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षी का या फिर जीव जंतु का। जल संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा तालाब, पोखर, आहर, पईन एवं चेकडैम की 1093 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। गया, राजगीर, नवादा और बोधगया में गंगा नदी के जल को पेयजल के रुप में पहुंचाने को लेकर काम किया जा रहा है। हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से 9 अगस्त 2020 तक 2.51 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाये गये हैं। बिहार में पर्यावरण के प्रति सभी लोग जागरुक हैं। 19 जनवरी 2020 को राज्य में 18 हजार किलोमीटर से अधिक की मानव श्रृंखला में जल–जीवन–हरियाली अभियान के समर्थन में 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आप सभी वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों से आग्रह है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी कार्य कर रही है। आप सब इसमें सहयोग करें और छात्र–छात्राओं समेत अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, पूसा, डॉ0 राजेन्द्र केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूर्वी क्षेत्र पटना के केंद्रों के माध्यम से जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसे राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित करने को लेकर योजना बनाई जा रही है। फसल अवशेष (पराली) जलाने से हो रहे पर्यावरण को नुकसान से बचाव के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में कृषि यंत्रों, हैप्पी सीडर एवं जीरो टिलेज मशीन, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ रीपर एवं स्ट्रॉ बेलर तथा रीपर कम बाइंडर यंत्र पर 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि के तहत चिन्हित गांवों में हैप्पी सीडर से गेहूं की खेती के फलस्वरुप किसानों के शुद्ध आय में 21 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा किनारे 2.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी कृषि के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि वागवानी मिशन 23 जिलों में शुरु की गई है बाकि बचे जिलों में राज्य सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के कृषि क्षेत्र में और प्रगति के लिए आप सब वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री प्रेम कुमार, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी, सचिव कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन श्री एन0 सरवन कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉ0 अजय कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर के सांसद श्री अजय कुमार मंडल, विधायक श्री लक्ष्मीकांत मंडल, विधायक श्री सुबोध राय सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, छात्र–छात्रायें जुड़े हुए थे।

******